letter2:letter1.qxd 9/26/2010 8:41 PM Page 106

व प्रधानमंत्री पर ख़र्च की गई धनराशि 122.52 करोड़ रुपये थी, जो लोकसभा के कुल ख़र्च का आधा और राज्य सभा पर ख़र्च होने वाली राशि से 30.39 करोड़ रुपये ज्यादा था। इस पर यदि एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) पर होने वाले 79.46 करोड़ रुपये के ख़र्च को भी जोड़ा जाए तो यह लोकतंत्र हमारी मंत्रिपरिषद, संसद और राष्ट्रपति कार्यालय को बेहद ख़र्चीले लोक संस्थान बना देता है।

मैं राष्ट्रपति को इस विवाद में नहीं घसीटना चाहता। अतः उनके व्यक्तिगत वेतन व सुविधाओं पर कुछ नहीं कहूंगा परंतु मैं इस बात पर दुःख़द आश्चर्य जरूर प्रकट करूंगा कि जब देश में एक ओर करोड़ों लोग बिना किसी छत के जीने को मजबूर हैं, ऐसे में राजप्रासादनुमा राष्ट्रपति भवन के रख़रख़ाव पर इतना धन ख़र्च किया जाए। मैं इसमें कोई औचित्य नहीं देखता कि रहने के लिए एक व्यक्ति या परिवार को 350 कमरों वाला घर दिया जाए।

उपरोक्त तथ्यों व स्थितियों ने लोगों के मन में संसद के प्रति सम्मान को कम करने में अपना योगदान दिया है। इस संदर्भ में इस बात पर भी जोर देना होगा कि संसद की व्यवस्था का निर्धारण करने वाले संविधान के अनुच्छेद 79 से 123, जिसमें संसद का विशेषाधिकार भी शामिल है, ऐसी किसी व्यवस्था की बात नहीं करते जो इसके नियंत्रण व संतुलन को भीतर की बजाए बाहर से संचालित कर सके। दुःख़ है कि अभी यह काम होना बाकी है, अतः इस दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत है। इसमें सांसदों को केवल लाभ उठाने वाला बनाने से रोकने के लिए एक आम बहस शुरू करने की जरूरत है। साथ ही इनके वेतन व भत्तों के संबंध में पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। ताकि लोगों की नजरों में संसद की खोई गरिमा व प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सके।

मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि यदि इस तरह की दख़लंदाजी पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतंत्र की चूलें हिला देगा और जनता के मन में इसके प्रति आस्था कम करेगा। अतः आप सभी बुद्धिजीवियों एवं विचारनायकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय पर गहराई से सोचें और इस मुद्दे को उचित मंच पर उठाएं। ताकि इस संबंध में एक निश्चित परंपरा और संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जा सके, जो वैधानिक हो।

परंतु निश्चय ही मैं अपनी बात को निराशा के बिंदु पर ख़त्म नहीं करना चाहता। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार व लागू किए गए सामुदायिक व व्यक्तिगत प्रयासों से स्वावलंबन पर आधारित ग्रामीण विकास के चित्रकूट मॉडल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि समुचित संस्थागिक सहयोग दिया जाए तो हमारा ग्रामीण समुदाय अपनी आंतरिक समस्याओं से निजात पा सकता है। इतना ही नहीं यह निरंतर विकास के नए सोपान चढ़ सकता है और समकालीन बाजार तथा नवीन तकनीकों का सहारा लेकर स्वरोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा दे सकता है।

अब समय आ गया है कि विकास की ऐसी नीति अपनाएं जिसमें जनसक्रियता सुनिश्चित हो और लोक. हित के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ऐसा शासन तंत्र हो जिसमें जिम्मेदारी का भाव समाहित हो। इससे हमें अपने लोगों की आंतरिक क्षमताओं तथा कुछ नया करने की उनकी ललक को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के द्वारा सामाजिक समानता एवं न्याय आधारित विकास प्राप्त किया जा सकता है। इससे लोकतंत्र पुष्ट हो सकेगा जिसके सहारे विकास के ऊंचे सोपान न्यूनतम ख़र्च में चढ़ना भी संभव होगा।

मेरा निवेदन है कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारियों व सामाजिक बुराईयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए देश कौन सा विकास मॉडल अपनाएं, इस बारे में एक सार्थक आम बहस शुरू की जानी

आज सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों व पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलने वाले भत्ते व सुविधाएं भी इसी 'प्रिवि पर्स' का नया अवतार नजर आते हैं।

नानाजी की पाती युवाओं के नाम

चाहिए। दीनदयाल शोध संस्थान ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसमें आम लोगों की पहल और उनके पुरुषार्थ को बढ़ावा दिया जाता है। इसी भावना और उत्साह को लेकर यह संभव हुआ है कि आज चित्रकूट के आस-पास के 80 गांवों ने-

- शून्य बेरोजगारी
- शून्य गरीबी
- शून्य कुपोषण
- शून्य मुकदमेबाजी
- और साफ-सुथरे व हरे-भरे गांवों

के सपने को सच कर दिखाया है। वह भी निर्धारित समय सीमा से पूर्व।

उल्लेखनीय है कि दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में गरीब परिवारों, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से क्यों न हों, की सक्रिय भूमिका से उन्हें स्वावलंबी बनाने के प्रयासों में दुर्लभ पूरकता भी हासिल कर ली है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन लक्ष्यों को संस्थान ने निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया। संस्थान अब इस दशक के अंत तक इन लक्ष्यों को 500 गांवों में प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। और यह चमत्कार किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया है। इसके के लोगों ने दीनदयाल शोध संस्थान के निस्वार्थी व उत्साही कार्यकर्ताओं के निकट सहयोग से इस महती लक्ष्य को पूरा किया है। संस्थान तो केवल प्रेरणा देने का काम करता है। वास्तविक ऊर्जा व क्षमता तो लोगों के भीतर है।

पुरानी पीढ़ी के कई उद्योगपतियों को याद होगा कि सन् 1977 में सक्रिय राजनीति से सन्यास लेते समय मैंने उनसे सामुदायिक विकास के कार्यों में सक्रिय भागीदारी देने का आग्रह किया था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के उद्योगपतियों में विलक्षण प्रबंधकीय प्रतिभा और क्षमताएं हैं। औद्योगिक घरानों की उत्तरोत्तर प्रगति में उनके ये गुण परितक्षित भी होते हैं। लेकिन सामाजिक व सामुदायिक गतिविधियों में उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 1977 में मैंने जब फिक्की के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंघानिया से अपने संगठन के माध्यम से उद्योगपतियों को सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए प्रेरित और संगठित करने का निवेदन किया था। उसके परिणामस्वरूप कई उद्योग. पति अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं व प्रयासों के साथ इसके लिए आगे भी आए थे। परंतु दुर्भाग्य से यह प्रयास एक सामूहिक गति नहीं प्राप्त कर पाया। मैं एक बार पुनः सभी औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों का आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं और विकास के इस महायज्ञ में योगदान देने के लिए अपने सदस्यों को प्रेरित करें।

समय आ गया है कि हम विकास की ऐसी नीति अपनाएं जिसमें जनसक्रियता सुनिश्चित हो और लोकहित के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार शासन तंत्र हो।

शुभाकांक्षी

नानाजी देशमुख

(नाना देशमुख)